nt>
Title: Further discussion on recent developments affecting India's foreign policy. (Concluded)

11.15 hrs.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, नियम १९३ के अधीन श्री संगमा ने जो अल्पकालिक चर्चा मांगी थी, मैं उस बहस का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। विषय विदेश नीति से संबंधित है और विदेश नीति हमारे देश की सुरक्षा की नीति से भी जुड़ी है। यह बात सच है, मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि विदेश नीति पर इस देश में एक आम सहमति रही है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष विदेश नीति के क्षेत्र में बहुत कम उजागर होकर आते थे। गुट निरपेक्षता की नीति को सारे देश का, सब दलों का समर्थन प्राप्त था। भारत की परमाणु नीति क्या हो, यह भी चर्चा का विषय रहा है। उस पर भी एक आम सहमति रही है। मैं इस आरोप की स्वीकार नहीं करता कि आम सहमति में दरार डाल दी गई है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, वे कदम उठाए जाएंगे। इस सवाल को दलगत दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

चर्चा में यह कहा गया कि हमने परमाणु परीक्षण इसलिए किया कि हम सुरक्षा परिषद में सीट चाहते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करना भारत का सहज और स्वाभाविक अधिकार है। विश्व बदल गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए-नए देश आ गए हैं, नए-नए भूखण्ड आ गए हैं। उपनिवेशवाद ने पछाड़ खाई है। स्वतंत्रता की लहर आई है। आज का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा है, वह विश्व की वास्तविकता को प्रतिबिम्बित नहीं करता। क्या सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसी की दया पर निर्भर होनी चाहिए? क्या इसका निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होना चाहिए? हम इसके लिए परमाणु परीक्षण करें, यह हास्यास्पद बात है।

श्री संगमा ने इस बात पर भी बल दिया था और मैं उनसे सहमत हूं कि देश को जहां सैनिक दृष्टि से तैयार होना चाहिए, वहां आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की भी बड़ी आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा की आवश्यकता, इनमें अतर्विरोध नहीं है।

हम अपने साधनों का उत्तमता से उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षित भी रहे और राष्ट्र में समृद्धि भी आये लेकिन हम सुरक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते। पचास साल का अनुभवकाल हमारे सामने है। कई बार हमें आक्रमण का शिकार होना पड़ा है और विशाल भू-भाग खोना पड़ा है। उसे फिर से प्राप्त करने के लिये हम शान्तिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता अपना रहे हैं। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिये सुरक्षा को मज़बूत करना ज़रूरी है। जैसा मैंने निवेदन किया, अगर हम अपने साधनों का ठीक तरह से उपयोग करें तो सुरक्षा के तकाज़ों को भी पूरा किया जा सकता है और देश को समृद्धि की ओर भी ले जाया जा सकता है। यह कहना कि बाज़ार में टमाटर और प्याज़ के दाम बढ़ गये हैं क्योंकि पोखरण में परीक्षण किया गया था, यह व्यंग-विनोद के लिये ठीक है मगर इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के ज़माने में एक परीक्षण हुआ था। २४ साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे कि जिन्होंने एटमी हथियारों के अम्बार लगा रखे हैं, वे अपने अम्बार खत्म करें और ऐसे विश्व की रचना हो जिसमें एटमी हथियार न हों, ऐसा हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। पोखरण के बाद, जो अणु शस्त्रधारी देश हैं, उन पर इस बात का दबाव पड़ रहा है कि वे आणविक निःशस्त्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ायें।

पिछले कुछ दिनों में हमें जिन-जिन सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला, इसके साथ यह सवाल भी जुड़ा हुआ है। कई माननीय सदस्यों ने एक बात को दोहराया कि भारत अलग-थलग पड़ गया है। कहां अलग-थलग पड़ गया है? सौ करोड़ के देश को कौन अलग कर सकता है? कैसे भारत की उपेक्षा की जा सकती है? चाहे वह गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो, मनीला की बैठक हो या सार्क देशों का शिखर सम्मेलन हो, उसमें हमारी भूमिका, उसमें अन्य देशों के साथ हमारी बातचीत सार्थक रही है। क्या यह अलग-थलग पड़ने की निशानी है?

नैम' सम्मेलन में इस बात का प्रयास हुआ कि अणु परीक्षण के लिए हमारा नाम लेकर हमारी आलोचना की जाए। सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की यह परम्परा भी नहीं रही है।

अभी कोलम्बो में सार्क सम्मेलन हुआ था। सार्क सम्मेलन के बारे में इतना कहना काफी होना चाहिए कि जो हमें अलग-थलग करना चाहते थे, वे स्वयं वहां अलग-थलग हो गये। सार्क का गठन आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए, परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए, मुक्त व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए और फिर आगे जाकर एक साझा बाजार बनाने के लिए हुआ है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम कोलम्बो में उठाये गये। लेकिन पाकिस्तान की उन कदमों में रुचि नहीं थी। वह कोलम्बो में एक ही रट लगाये रहे, यह भी तर्क दिया गया कि जब तक आपस के विवाद खत्म नहीं होंगे, तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। थोड़े बहुत विवाद हमेशा रहेंगे और वह केवल हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही नहीं हैं और भी देशों के बीच में हैं। उन विवादों को वार्ता के द्वारा हल करने की दिशा में कदम उठना चाहिए और उठते रहते हैं। लेकिन उन विवादों के हल को एक शर्त बना देना कि तब तक आर्थिक सहयोग का कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे की सहायता कोई अर्थ नहीं रखती, अगर विवाद हल नहीं होते, यह चिंतन की दिशा गलत है। हम शांति के समर्थक हैं, विवादों को वार्ता द्वारा हल करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि इन विवादों के कारण आर्थिक विकास रुकना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या इस देश में, इस क्षेत्र में निवास करती है, जो आर्थिक दृष्टि से अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त है और सार्क एक महान प्रयोग है, सही दिशा में प्रयोग है। उससे द्विपक्षीय सम्बंधों में भी सुधार हुआ है। शिखर सम्मेलन के अलावा कोलम्बों में जो समय उपलब्ध था, उसमें द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, लेकिन वे सम्मेलन का भाग नहीं थीं और हमने इस बात का विरोध किया कि इनका समावेश औपचारिक ढंग से एजेंडे में नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर एक मदारी का पिटारा खुल जायेगा। हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही विवाद नहीं है और देशों के बीच में भी विवाद हैं और सार्क सम्मेलन ऐसे विवादों पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए, अनौपचारिक वार्ता के लिए समय देता है।

कल श्री इंद्रजीत गुप्त ने बंगलादेश में जो असम के आतंकवादी आश्रय पाये हुए हैं, उनका मामला उठाया था।

अध्यक्ष महोदय, बंगलादेश के प्रधान मंत्री से इस बात की चर्चा हुई है और हमने मांग की है कि उनके कब्जे में जो अपराधी हैं जिनके ऊपर भारत में मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें हमें सौंप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। हम उन्हें जेलों में बंद रखे हुए हैं और जब कानूनी प्रक्रिया हमें

इजाजत देगी, तो हम उन्हें जरूर आपको सौंपेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह से श्रीलंका के साथ मछुआरों का सवाल है।

महोदय, ये सम्मेलन हमें अवसर देते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाए। इस तरह के प्रश्नों पर विचारों का आदान-प्रदान हो। सार्क के शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख भूमिका थी। भारत के अलग-थलग पड़ने का सवाल ही नहीं है। मनीला में दो बैठकों में जो कुछ हुआ, सबने देखा कि सदस्य देशों के नेताओं से हमारे प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हुई। भारत की सुरक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ी है। मैटर आफ अंडरस्टेंडिंग में बहुत से माननीय सदस्य अभी ११ मई तक अपने को सीमित रखे हुए हैं, केन्द्रित रखे हुए हैं। दुनिया उससे आगे बढ़ गई है।

महोदय, परमाणु परीक्षण के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए और किस तरह से दूरगामी और विश्वव्यापी हल निकाला जाए, अब इस पर चर्चा हो रही है। हर सम्मेलन में यह कहा गया कि आणविक निशस्त्रीकरण एक विश्वजनीन (ग्लोबल) समस्या है। इसको टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। जेनेवा में आठ देशों ने अलग होकर एक वक्तव्य दिया जिसमें जो बड़े-बड़े देश हैं, वे औरों से कहते हैं कि आप अणु शस्त्र मत बनाइए, हथियारों की दौड़ में शामिल मत होइए, वे स्वयं अपने आचरण को देखें, वे स्वयं अपने हथियार कम करें। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार एटोमिक हथियारों का विनाश होना चाहिए, निर्मूलन होना चाहिए। यह आवाज आज जोर पकड़ रही है। द्विपक्षीय वार्ता में भी ये मामले उठे थे।

महोदय, जापान के पूर्व प्रधान मंत्री, अब तो वहां नए प्रधान मंत्री आ गए हैं, उन्होंने मुझे पत्र लिख कर मेरे पत्र के लिए धन्यवाद दिया है और कहा कि भारत की सिक्योरिटी कंसर्नस को अब हम बेहतर समझ रहे हैं। जापान वह देश है जिसके ऊपर अणु बम डाला गया था, जिसकी विभीषिका से अभी तक लोग त्रस्त हैं। हमने आक्रमण के लिए परमाणु विस्फोट नहीं किया, बचाव के लिए किया है।

आत्मरक्षा के लिए किया है। कोई हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को फिर से खतरे में न डाल दें इसलिए डिटरेंट के रूप में और डिटरेंट भी मीनिमम डिटरेंट हमारी नीति का आधार है। इसलिए हमने ऐलान कर दिया कि अब हम भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में इस तरह की आवश्यकता पड़नी भी नहीं चाहिए। यद्यपि सी.टी.बी.टी. इस बात की इजाजत देती है और एन.पी.टी. पर दस्तखत करने के बाद अगर कोई देश यह समझता है कि उसके सर्वोच्च राष्ट्र हित के लिए खतरा पैदा हो गया है, आशंका पैदा हो गयी है तो वह उचित कदम उठा सकता है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): दस्तखत करने की भूमिका है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हम तो यह चाहते हैं कि मोरेटोरियम को एक कानूनी रूप दे दिया जाये, कानूनी दायित्व दे दिया जाये। हमने यह भी कहा कि हम अणु अस्त्रों का पहले उपयोग नहीं करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : जब दूसरा हम पर हमला कर देगा तो फिर क्या रहेगा? ... (व्यवधान) तब क्या आप चलाने लायक रहेंगे?

... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि वह तर्कसंगत न हो।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं, जब दूसरा चला देगा तब क्या हम चलायेंगे? हम पर खतरा हुआ

... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: दूसरा क्यों चलायेगा?

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह करेंगे कुछ और कहेंगे कुछ।

... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: दूसरा क्यों चलायेगा?

... (व्यवधान)

देश की जनता को सच्चाई बताई गयी है और सच्चाई के अनुसार आचरण किया जा रहा है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप दोस्ती कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अगर दूसरे देश उपयोग करेंगे तो हम कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, यह धारणा मन से निकाल देनी चाहिए। हमारा अणु शस्त्र सम्पन्न होना ही एक डिटरेंट है। हमला नहीं होना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह कहिये कि दोस्ती हो जायेगी तो चलाना नहीं पड़ेगा।

... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इस तरह की संधि

... (व्यवधान)

कई देशों के साथ करने को भी हम तैयार हैं।

... (व्यवधान)

कोलम्बो में यह मामला उठा था कि जिन देशों के पास अणु शस्त्र नहीं है, उनको आप सुरक्षा का आश्वासन दीजिए। मैंने कहा कि जिनके पास अणु बम नहीं है, उनके ऊपर अणु बम का प्रयोग हो, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हम पहले प्रयोग करने वाले देश नहीं होंगे तो उन देशों के खिलाफ उसका उपयोग किया जाये, जिनके पास नहीं है, इसका तो कोई आधार नहीं रहता। यह भी जरूरी है कि निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाये।

पाकिस्तान न केवल कश्मीर को केन्द्र बिन्दु बनाकर अपनी सारी कूटनीति चला रहा है मगर साथ-साथ वह इस बात पर भी बल दे रहा है कि नॉन-प्रौलीफरेशन के मामले को कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए। कश्मीर का विवाद पचास साल पुराना है। उसे वार्ता के द्वारा द्विपक्षीय ढंग से हल करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दुनिया के किसी देश में, चाहे वह फिर जी ५ के हों या जी ८ के हों, इस बात को स्वीकार नहीं किया कि प्रौलीफरेशन के मुद्दे को कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए। कश्मीर एक अलग विवाद है और आणविक निशस्त्रीकरण अपने में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पाकिस्तान केवल कश्मीर पर बात करना चाहता है और किसी मुद्दे पर नहीं। क्यों? दोनों देशों की बीच में और भी मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर बात क्यों न हो? हम पड़ोसी हैं, हमें साथ रहना है। केवल कश्मीर के मुद्दे पर बात क्यों?

कल सोज़ साहब बता रहे थे कि कश्मीर में किस तरह की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। वहां शांति है। चुनाव हुए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा सकुशलता से चल रही है। यह कहा जाता है कि कश्मीर एक फ्लैश पाइंट है। हां, अगर पाकिस्तान छोटे-मोटे उपद्रव कराकर विश्व का ध्यान खींचने के लिए कुछ कदम उठाना चाहता है तो मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि उसको सफलता मिलने वाली नहीं है। लेकिन मैं कभी-कभी सोचता हूं कि आखिर कश्मीर पर बल क्यों है। पाकिस्तान अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान यथास्थिति को बदलना चाहता है। पाकिस्तान के शासकों के गले के नीचे यह बात नहीं उतर रही है कि ऐसा प्रदेश जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान हैं, वह भारत के साथ रहे। उन्होंने सैकुलरवाद को स्वीकार नहीं किया, यह उनका मामला है। लेकिन हमारे लिए कश्मीर केवल एक भूखंड नहीं है, भूखंड तो है ही महत्वपूर्ण है लेकिन उसके साथ कुछ आदर्श भी जुड़े हैं, कुछ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। इसलिए केवल कश्मीर पर बात करो, हमने इससे इंकार किया और यह इंकार मेरी सरकार का इंकार नहीं है, जो पिछली सरकार थी, उसके द्वारा लिया गया रवैया है। एक एजैंडा तैयार हुआ था। उस एजैंडे पर बात करने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तान पीछे हट गया। वे हमारे ऊपर पीछे हटने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें सच्चाई नहीं है। हमने कहा कि कश्मीर पर हम बात करने के लिए तैयार हैं मगर उसके साथ और भी जो मसले हैं, उनको भी वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। एक लम्बी दृष्टि से बात करने की जरूरत है।

लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। कोलम्बो में चलते-चलते उन्होंने हम लोगों के हाथ में कागज दे दिया, जिसको पढ़ने से साफ प्रकट होता है कि वार्ता में उनकी रुचि नहीं है। वे संसार का ध्यान खींचकर कश्मीर को अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाना चाहते हैं, लेकिन और कोई देश उनकी इस बात से सहमत नहीं है, अरब देश भी, पी-५ और जी-८ के देश भी, यहां तक कि चीन ने भी कहा है कि आपस की बातचीत से कश्मीर का, जम्मू-कश्मीर का मसला हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने जो विश्वास बनाने के सुझाव रखे हैं, कॉन्फीडेंस बिल्डिंग मैजर्स, उनमें एक सुझाव यह है कि हुर्रियत को कश्मीर की प्रतिनिधि संस्था मानकर भारत सरकार उसके साथ बातचीत करे। क्या कोई भारतीय इस बात को स्वीकार कर सकता है? कश्मीर लोकतंत्र भारत का अंग है, अभी वहां चुनाव हुए हैं, चुनाव कमीशन की देख-रेख में चुनाव हुए हैं। मगर एक उदाहरण से मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान वार्ता में रुचि नहीं रखता। लेकिन हम अपना प्र यास जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरें, यह आवश्यक है। यह सही है कि सुधार की भावना दोनों तरफ होनी चाहिए, लेकिन भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है।

मनीला में चीन के प्रतिनिधि के साथ जो बातचीत हुई, उससे बीच में जो गठान पड़ गई थी, उसको खोलने में मुझे विश्वास है, मदद मिलेगी। भारत के कुछ नेताओं के वक्तव्यों का हवाला देकर हमारे चीनी मित्र अपना रोष प्रकट करते हैं। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि आप समाचार-पत्रों में छपे हुए वक्तव्यों के आधार पर

निर्णय न निकालें। हमारे रक्षा मंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि चीन उनका पहला एक नम्बर का शत्रु है, इसका खंडन भी भेजा था लेकिन ... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : जब आप लोगों का, भारत सरकार का रिएक्शन आया तो पटना में छह दिन के बाद जाकर बोले कि हम ऐसा नहीं बोले हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बोले न? बोले। लालू प्रसाद जी हमारी बात की पुष्टि कर रहे हैं। उनको शिकायत इतनी है कि छह दिन बाद बोले।

श्री लालू प्रसाद : नहीं, खंडन किया। छह दिन के बाद पटना में खंडन किया, जब विदेश विभाग का प्रवक्ता बोला कि मंत्री का, भारत सरकार का वह बयान नहीं है। मंत्री को तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने उन चीजों का हवाला चिट्ठी में भी किया है। चिट्ठी में आपने लिखा है, पता कर लीजिए।

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया): चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए यह बात कही गई।

... (व्यवधान)

मैंने सुना नहीं, अध्यक्ष जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अमेरिकी राष्ट्रपति को

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : प्रधान मंत्री जी आपके मंत्री गलती करते हुए जब पकड़े जाते हैं तो अखबारों पर मढ़ देते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह तो आपका और हमारा पुराना तरीका है। अध्यक्ष महोदय, जिस चिट्ठी का बहुत हवाला दिया जा रहा है, उस चिट्ठी में जहां चीन से उत्पन्न होने वाली आशंकाओं का उल्लेख है, वहां इस बात का भी उल्लेख है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हुआ है और हम सम्बन्धों में और भी सुधार चाहते हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : फिर चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि कुछ मामले ऐसे हैं हमारे और चीन के बीच में जो तय होने बाकी हैं।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is this? Let him complete. Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Prime Minister, please clarify the Government of India's stand on this. It is a very important matter. The relation between the Government of India and China should be proper and harmonious...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee, let him complete.

... (Interruptions)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं इससे सहमत हूं कि भारत के चीन के साथ सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, सहयोगात्मक होने चाहिए। उनको सहयोगात्मक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, वे हम उठा रहे हैं। जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीमाओं का प्रश्न है, जिस पर बातचीत चल रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जरूर चलनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः हमने पाकिस्तान से भी यह कहा था कि समस्याओं को हल करने का एक रास्ता यह है कि जो विवाद का आप कोई मुख्य मुद्दा समझते हैं, वह तत्काल हल नहीं होगा। उसको थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। हम और आप व्यापार बढ़ाएं, लोगों के आने-जाने में वृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि में योगदान दें, तो स्थिति सुधरेगी, सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनेंगे। उसमें फिर कठिन से कठिन समस्या को हल करना भी सरल होगा। चीन के साथ यही नीति अपनाई गई है। इस सम्बन्ध में हम और भी अपने प्रयास जारी रखेंगे। जो चिंताएं हैं, वे भूखंड को लेकर हैं, सीमाओं को लेकर हैं, उन्हें भी बातचीत से हल करना पड़ेगा।

श्री लालू प्रसाद : मानसरोवर और कैलाश पर्वत के मामले में भी आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो उधर रथ ले जाइए, शंकर जी को ले आइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः इस चर्चा में सी.टी.बी.टी. का मामला भी बड़े जोरदार तरीके से उठाया गया था। मुझे इस सम्बन्ध में जो कुछ कहना है वह ठीक रूप से उद्धृत हो, इसके लिए मैं अंग्रेजी भाषा का सहारा लेना चाहता हूं।

A number of hon. Members wished to know Government's position on the CTBT. After concluding the series of tests on May 13, India immediately announced a voluntary moratorium on further underground nuclear test explosions. In announcing this moratorium, India accepted the basic obligation of a test ban. In 1963 too, we had wanted a Comprehensive Test Ban Treaty. What the international community concluded instead was only a Partial Test Ban Treaty (PTBT). Eventually, India went along and became an original state party to the PTBT. That decision was taken in the broader national interest.

As hon. Members know full well, India, which first proposed a ban on testing in 1954, and as a country that remains committed to global nuclear disarmament, could hardly have acted otherwise. In announcing the moratorium, we reflected our own commitment to disarmament as also addressed the general wish of the international community. Naturally, India reserves the right to review that decision if in its judgement extraordinary events take place that jeopardise India's supreme national interests. The CTBT also gives the same right to every country. We also announced then our willingness to move towards a de jure formalisation of our voluntary undertaking. Ways and means of doing this are being explored through bilateral discussions with key interlocutors. These dialogues have been undertaken after satisfying ourselves that India no longer requires to undertake nuclear explosions. We can maintain the credibility of our nuclear deterrent in the future without testing. India remains committed to this dialogue with a view to arriving at a decision regarding adherence to the CTBT. In 1996, we stayed out of the CTBT principally with national security as our only guide. That remains entirely unaltered.

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर हम अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में फैसला करेंगे और सदन को पूरी तरह विश्वास में लिया जाएगा।